



दिल्ली हाई कोर्ट

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा है कि दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार और अन्य के खिलाफ पूर्व तन नदिशालय के अधिकारी की अवमानना याचिका पर न सिरे से फैसला किया जा इस अधिकारी का आरोप है कि नीरज कुमार और अन्य ने उसके खिलाफ झूठे आरोप लगा

जसकी वजह से उन्हें 36 दिन सलाखों के पीछे गुजारने प शीर्ष अदालत ने कहा है कि हाई कोर्ट ने अशोक कुमार अग्रवाल की अवमानना याचिका खारज करते वक्त सभी संबंधित तथ्यों पर गौर नहीं किया इसलिए उसे न सिरे से इस पर फैसला करना चाहिए

न्यायमूर्ति बी स चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा- हमारी सुविचारित राय है कि दोनों ही पक्षों ने तथ्यों और कानूनी मुद्दों को उठाया था हाई कोर्ट के सभी संबंधित तथ्यों, विशेषकर जब अपीलकर्ता (अग्रवाल) ने आरोप लगाया था कि प्रतिवादियों ने अदालत को गुमराह करके उसकी आजादी के खतरे में डालकर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया, पर गौर करना चाहिए था परिणामस्वरूप हम फैसला और आदेश रद्द करते हुए पक्षों के सभी तथ्यात्मक और कानूनी बंटियों का जवाब देने के लिए मामला न सिरे से फैसले के लिए हाई कोर्ट वापस भेज रहे हैं

इस अधिकारी का कहना था कि जांच अधिकारियों ने महत्वपूर्ण तथ्य अदालत से छिपा जसकी वजह से उसे 36 दिन न्यायिक हरिस्त में बिताने प शीर्ष अदालत ने अलग से अपने फैसले में अग्रवाल के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई वापस लेने का आदेश दिया है अग्रवाल के 13 साल पहले नलिंबति किया गया था अग्रवाल ने गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए अवमानना याचिका दायर की थी अग्रवाल के दो पासपोर्ट रखने और 10 से 14 फरवरी 1999 के दौरान सगिपुर की यात्रा करने के शक में गरिप्तार किया गया था भारतीय अधिकारियों की प ताल के दौरान अग्रवाल की यात्रा की पुष्टि इंटरपोल सगिपुर ने की थी लेकिन बाद में इंटरपोल ने उन्हें बताया कि उनकी दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत थी

दिल्ली के ककरोबारी ने अग्रवाल के खिलाफ शकियत की थी जसमें आरोप लगाया गया था कि फजी दस्तावेजों के आधार पर उसे फंसाया जा रहा है अग्रवाल की तलाश में इंटरपोल के जरि नोटिस जारी किया गया था क्मोंक वह फरार था अग्रवाल के 23 दिसंबर 1999 के सहारनपुर से गरिप्तार किया गया था जहां वह क होटल में छद्म नाम से रह रहा था